



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 1983/ अग्रहायण 23, 1905

No. 207] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 1983/AGRAHAYANA 23, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय
(न्याय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1983

सं. 46/2/81-न्याय :—यतः उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक बेंच की स्थापना की मांग से उत्पन्न सभी पहलुओं पर तथा राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने अपने तारीख 4 सितम्बर, 1981 के संकल्प सं 46/2/81-न्याय के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश, श्री जसवन्त सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था ;

और यतः आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निर्धारित समय समाप्त हो गया है और आयोग ने समय बढ़ाए जाने की मांग की है ;

और यतः गोहाटी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की बेंचें न्यायालयों के मूल स्थानों से इतर स्थानों

पर स्थापित किए जाने की, समय-समय पर, की जा रही मांगों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों ने भारत सरकार को या तो इन बेंचों की स्थापना किए जाने के बारे में सहमत होने का अनुरोध किया है या यह सुझाव दिया है कि ऐसी मांगें आयोग को भेज दी जाएं ,

अतः अब, भारत सरकार ने आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का समय दिसम्बर, 1984 की 13 तारीख तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, बढ़ाए जाने और आयोग से यह भी अपेक्षा करने का निर्णय किया है यह उच्च न्यायालयों के मूल स्थानों से इतर स्थानों पर उनकी बेंचों की स्थापना करने के सभी पहलुओं की भी जांच करे और रिपोर्ट दे और इस सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मान-दण्डों तथा विशेषकर पूर्वोक्त उच्च न्यायालयों की स्थायी बेंचों की स्थापना की मांगों की जांच करे और रिपोर्ट दे ।

2 तदनुसार, आयोग दिसम्बर, 1984 की 13 तारीख को या इससे पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ।

कैलाश चन्द्र कनकन, निदेशक

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COM-
PANY AFFAIRS

(Department of Justice)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th December, 1983

No. 46/2/81-Jus.—Whereas the Government of India vide its Resolution No. 46/2/81-Jus., dated the 4th September, 1981 had set up a Commission with Shri Jaswant Singh, Retired Judge, Supreme Court of India as Chairman, to consider all aspects arising out of the demand for the constitution of a Bench of the Allahabad High Court for the western districts of Uttar Pradesh and the various aspects of the recommendation made by the State Govt.;

And Whereas the time fixed for submission of the report by the Commission has expired and the Commission has asked for extension of time;

And Whereas on demands being made, from time to time, for the establishment of permanent

benches of the High Courts of Gauhati, Karnataka, Madhya Pradesh and Madras at places other than their principal seats, the State Governments concerned have either requested the Government of India to agree to the establishment of such benches or have suggested that such demands be referred to a Commission;

Now, Therefore, the Government of India have resolved to extend the time for submission of its report by the Commission upto and including the 13th day of December, 1984 and to require the Commission to examine and report, also, on all aspects of the general question of having benches of High Courts at places other than their principal seats and on the broad principles and criteria to be followed in this regard and in particular on the demands for the establishment of the permanent benches of the High Courts aforesaid.

2. The Commission will accordingly submit its report on or before the 13th day of December, 1984.

K. C. KANKAN, Director